उत्तर प्रदेश में रोजगार संबंधी स्कीम

2798. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में सभी लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने हेतु कौन-कौन सी स्कीमें चलाई जा रही है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ग) प्रत्येक स्कीम के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या था और विगत तीन वर्षों के दौरान इन लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल):

(क) उत्तर प्रदेश में लोगों के लिये रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना नामक दो प्रमुख योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले ग्रामीण गरीब परिवारों के लिये स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराकर कार्यान्वित किया जा रहा है और जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प-रोजगार वाले पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिये अतिरिक्त लाभकारी रोजगार जुटाना है।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत आबंटित निधियों, निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त हुई उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों के लिये उत्तर प्रदेश में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आबंटन, लक्ष्य और उपलब्धियां

	कुल आबंटन (लाख रुपये में)	लक्ष्य (सहायता किए गए परिवारों की संख्या)	उपलब्धि
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
1989-90	14727.97	6,73,362	6, 30, 024
1990-91	14727.97	4,68,144	5,08,840
1991-92	13857.12	4 43,427	4,62,259

(लाख रुपये में)	कुल आवंटन	लक्ष्य (रोजगार सृजन लाख श्रमदिनों में)	उपलब्धि
जवाहर रोजगार योजना	53452.72	1436.28	1624.95
1989-90	48538.62	1703.11	1628.27
1990-91	44547.01	1472.69	1562.14
1991-92			

गुजरात में कुओं की खुदाई पर खर्च की गई धनराशि

2799. **श्री राम सिंह राठवा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में जवाहर रोजगार योजना के लिए आवंटित राशि का 20 प्रतिशत भाग कुओं की खुदाई पर खर्च किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इस योजना के अन्तर्गत किए गए कार्य का कोई लेखा-जोखा नहीं रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और विगत दो वर्षों के दौरान गुजरात में खोदे गए कुओं की जिलावार संख्या कितनी है तथा इस कार्य पर जवाहर रोजगार योजना कोष में से कितनी धनराशि खर्च की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी):

(क) और (ख) जवाहर योजना के अन्तर्गत 20% निधियां दस लाख कुओं की योजना के लिए निर्धारित की गई है जिसमें खुले सिंचाई कुओं, सिंचाई तालाबों, जल एकत्रीकरण ढांचों आदि जैसी लघु सिंचाई योजनाओं की व्यवस्था करना और साथ ही अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मुक्त बंधुआ मजदूरों की भूमि का विकास करना शामिल है। 1990-91 और 1991-92 के दौरान गुजरात राज्य में दस लाख कुंओं की योजना के कार्यान्वियन हेतु रिलीज की गई राशि और सूचित खर्च नीचे दर्शाया गया है:—

(लाख रुपये में)

वर्ष	रिलीज की गई राशि	खर्च की गई राशि
1990-91	1618.14	807.95
1991-92	1109.48	1964.66

(ग) व (घ) दस लाख कुंओं की योजना के अन्तर्गत गुजरात में 1990-91 में 3331 और 1991-92 में 6364 कुंओं का निर्माण किया गया था। दस लाख कुंओं की योजना के अंतर्गत निर्मित कुंओं की संख्या के बारे में जिलावार सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। 1990-91 और 1991-92 के दौरान दस लाख कुओं की योजना पर किए गए जिलावार खर्च को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1990-91 और 1991-92 के दौरान दस लाख कुओं की योजना पर किया गया जिला-वार खर्च

(लाख रुपये में)

जिले का नाम	1990-91	1991-92
1.अहमदाबाद	35.67	54.18
2. अमरेली	6.93	8.91
3. बनासकांठा	37.76	74.60
4. भड़ौच	23.50	84.56
5. भावनगर	13.30	21.51
6. डांग	8.46	35.97
7. गांधी नगर	—	7.64
8. जामनगर	11.80	17.00
9. जूनागढ़	33.10	91.29
10. कच्छ	8.74	101.96
11. खेड़ा	37.68	58.93
12. मेहसाना	—	**
13. पंचमहल	211.02	581.94
14. राजकोट	20.52	42.09
15. सबरकंठा	71.96	58.40
16.सूरत	42.54	136.26
17. सुरेन्द्र नगर	10.33	25.16
18. बड़ोदरा	45.67	152.46
19. बलसाड़	189.97	411.80
योग:	807.95	1964.66

**उपलब्ध नहीं है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों को आवंटित भूमि का कब्जा

2800. **श्री राम सिंह राठवा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों को उन्हें आवंटित की गई भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब्जा न देने के राज्यवार मामले कितने-कितने है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने उन्हें कब्जा देने के लिए क्या प्रयास किए है तथा इस संबंध में राज्य सरकारों को क्या निदेश जारी किए गए है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी): (क) और (ख) राज्य सरकारें यह सूचित करती रही हैं कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आवंटित भूमि का कब्जा उनको दिया जा रहा है।

(ग) भूमि राज्य का विषय होने के कारण केन्द्र